

प्रियवा,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवार्थ,

जिलाधिकारी,
पौड़ीगढ़वाल।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक १ नवम्बर, 2008

विषय:- स्थान श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिविल जज (जू0डि0) के न्यायालय, आवास एवं आवासीय भवनों हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0- 2866/20-जे0ए0(2007-08) दिनांक- 24-07-2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तहसील मुख्यालय श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिविल जज (जूनियर डिविजन) के न्यायालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु नॉन जेड0ए0खतीनी संख्या-3 एवं 4 मध्य 0.378 हे0 राज्य सरकार की भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15-02-02 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन न्याय विभाग उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की गयी है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
 - 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गयी है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पडी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
 - 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षक अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमत्त होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी स अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

पृ0प0संख्या-00-27/समदिनांकित/2008

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 2- महानिष्पक्षक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
- 3- निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय।
- 4- प्रभारी भीडिया केन्द्र सचिवालय।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सन्तोष बठोनी)
अनुराधिव।